



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—हाइ 3—उप-हाइ (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

२५५७

सं. 64]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 1987/माघ 24, 1908

No. 64]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 1987/MAGHA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वीं जाती है जिसे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

### प्रधिकार

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1987

बीमा

का. श्रा 80(ग)---केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबाह (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17-के द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (विकास कर्मचारिकरूप के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य जरूरी का सुधारस्थीकरण), स्कीम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनानी है अधिकारी:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिकरूप के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य जरूरी का सुधारस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 1987 है।

(2) यह 1 जनवरी, 1987 को प्रवृत्त हुई गयी जाएगी।

(3) यह ऐसे सभी विकास अधिकारियों को आगे होगी जो साधारण बीमा (विकास कर्मचारिकरूप के वेतनमानों और सेवा की अन्य जरूरी का सुधारस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संशोधन स्कीम, 1987 कहा गया है) के प्रारम्भ को तारीख को, कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में वै और जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् इस प्रकार नियुक्त किए जाने हैं।

2. साधारण बीमा (विकास कर्मचारिकरूप के वेतनमानों और सेवा की अन्य जरूरी का सुधारस्थीकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संशोधन कहा गया है) के वैया 3 में—

(1) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(1) "कंपनी" से वह कलेंडर वर्ष प्रभित्रैत है जिसके द्वारा विकास अधिकारी के कार्य निष्पादन का प्रक्रन्त किया जाता है और वह कार्य निष्पादन वर्ष के पश्चात् याला कलेंडर मात्र होगा।'

(2) खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(2) "मूल वेतन" से इस स्कीम में उत्तरवादी के में दिए गए वेतनमान में विकास अधिकारियों की समय ममता पर अनुज्ञा वेतन अधिष्ठेत्र है।'

(3) खंड (5) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(3) खंड (5) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(5) "कंपनी" से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया प्रारंभिक बंदनी लिमिटेड, ओरिएंटल इनश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या यूनाइटेड इंडिया इनश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अधिष्ठेत्र है।'

(4) खंड (7) और (8) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएँगे। अर्थात् —

'(7) "खंड" में किसी विकास अधिकारी पर, कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान, माध्यारण बीमा कारबाह को उपायत करने के लिए उपगत खंड अधिष्ठेत है और इसके अन्तर्गत, ऐसे विकास अधिकारी की सकल प्रत्यायित्वों के प्रतिशिक्षण, उस वर्ष के दौरान विकास अधिकारी को संवत्सरीकी अहंसाओं के लिए भत्ता, बाह्य (नात कोर) भत्ते, यात्रा और टेलीफोन पर व्यय बोनस या अनुग्रहपूर्वक संदाय, माध्यारण बीमा कारबाह उपायत करने के लिए किए गए दौरानों पर यात्रा व्यय भी हैं, किन्तु इनके अन्तर्गत भविष्य निष्पत्र में नियोजक का अधिकार नहीं है;

(8) कार्य निष्पादन वर्ष की बाबत, "खंड अनुपान" में विकास अधिकारी पर, उसके द्वारा उपाय अनुसूचित प्रीमियम आय में उपगत खंड के प्रतिशत के रूप में अविष्टक अनुपान अधिष्ठेत है;

(5) खंड (9) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

'(9) "विकास अधिकारी" से विकास कर्मचारीबन्द के दोस्रे सदस्य अधिष्ठेत हैं जो संशोधन मंत्री, 1987 के प्रारम्भ से दोनों पूर्व, निरीक्षक दोष I और निरीक्षक दोष II के रूप में वर्गीकृत किए गए थे या नियन्त्रक किये गए थे और ऐसे प्रारम्भ पर कम्पन विकास अधिकारी दोष I और विकास अधिकारी दोष II के रूप में वर्द्धित किए गए थे।'

(6) खंड II में,—

(i) "नए निवासियों के अधीन देय" खंड का ऊपर किया जाएगा, अर्थात् —

(7) खंड (14) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् —

(14) "परिचालन अधिकारी" से विकास अधिकारी द्वारा उपाय और प्रचालन अधिकारी अधिकारित करने के प्रयोजन के लिए आय का, उसमें से नियम रकम काढ़ने के पश्चात्, यदि कोई हो, अधिकारी अधिष्ठेत है—

(क) आय में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(i) पूर्व कार्य निष्पादन वर्ष की अनुसूचित प्रीमियम आय के 50% की दर पर संगठित प्रनश्चिन्ता जाविष के लिए आरक्षित; और

(ii) कर्त्ता निष्पादन वर्ष की अनुसूचित प्रीमियम आय और (ब) नियम रकम में सुमंगल कार्य निष्पादन वर्ष के लिए निम्नलिखित मद्दों के योग होंगे, —

(1) उपगत दावे, जो वर्ष के दौरान नहीं की गई दावों की रकम उपगत वर्ष के अंत में बकाया दावों की रकम में जोह कर और उसमें से पूर्व कार्य निष्पादन वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए उपबंध घटाकर संगठित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण— इस भंड में,—

(क) किसी एकल दावे से उद्भूत एक लाख रुपये से अधिक का दावा एक लाख रुपये तक सीमित होगा;

(ब) उपगत दावों की संगठना करते समय अनुसूचित प्रीमियम आय से अपवर्जित किसी कारबाह की बाबत दावों की हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(ii) प्रणालयकीय व्यवस्था के लिए अनुसूचित प्रीमियम आय का 10%;

(iii) विकास अधिकारी पर उपगत खंड;

(iv) अनुसूचित प्रीमियम आय पर संवत्सर या संदेश कमीशन;

(v) अनुसूचित प्रीमियम आय के 50% की दर पर वर्ष के अंत में अनुबंधित जोखिम की आरक्षित।

(14) "कार्य निष्पादन वर्ष" से बह कर्वेंद्र वर्ष अधिष्ठेत है जिसकी वार्ता कार्य निष्पादन अंकत पर विचार किया जाता है;

(8) खंड (15क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

'(15क) "पुनरीक्षित विवरण" में अनुसूची (क) में विवरितिविद्धि पुनरीक्षित वेतनमात्र और भत्ते अधिष्ठेत है,

(15ग) "पुनरीक्षित वेतनमात्र" से अनुसूची (क) में विवरितिविद्धि पुनरीक्षित वेतनमात्र अधिष्ठेत है;

(9) खंड (17) में, स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित उपसंह अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(ग) एक जनवरी, 1987 को प्रारम्भ होने वाले कार्य निष्पादन वर्ष में जब अनुपान के संबंध में, नीचे की सारणी के संबंध 2 में विविद्धि और उसके संबंध 1 में तद्दानी प्रतिलिपि में विविद्धि विवरण प्रधिकारी पर उपगत अनुपान हैः—

	मारणी	खंड अनुसूचित
	1	2
निम्नलिखित रायत पर	पैरा 11 और 13 के प्रनालन विकास अधिकारी	पैरा 11 और 13 में संबंध में नामु पिछ पैराओं के संबंध में नामु

(क) ऐसे नगर जिनकी

जनसंख्या 12 लाख से अधिक है और पण्डी और मारसा-गोवा का शहरी एकलीकरण

8% 7%

(ख) 5 लाख और उसमें अधिक

जनसंख्या वाले नगर, 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की राजधानियां और लंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लैपर

9% 8%

(ग) अन्य केन्द्र

11% 10%

परन्तु यह कि—

(क) कार्य निष्पादन वर्ष 1987, 1988 और 1989 के लिए, कम्पन 1.5%, 1.5% और 1% की छूट, मारणी में विविद्धि खंड अनुपान की अनुबंधित सीमाओं में अनुशात की जाएगी।

(ख) विकास अधिकारी द्वारा, किसी अधिकारी के हस्तांतर के दिन सीधे प्रभिप्रात्र प्रीमियम के आरे में, खंड 1% की छूट, पैरा 11 और 13 के उपबंधों के लागू करने के लिए अनुशात की जाएगी।

3. उक्त स्कीम के पैरा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अनुस्यापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"एक. पुनरीक्षित वेतनमात्र में मूल वेतन का नियत किया जाना :—

- (1) प्रत्येक विकास अधिकारी का, जिसे 31 दिसंबर, 1986 को नए निबंधनों के अधीन वेतनमात्र में रखा गया है, मूल वेतन अनुसूची छ में यथाविनिर्दिष्ट । जनवरी, 1987 से, सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमात्र में, तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।
- (2) प्रत्येक विकास अधिकारी का, जिसे 1 जनवरी 1987 को या उसके पश्चात् किन्तु संशोधन स्कीम, 1987 के राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व नए निबंधनों के अधीन वेतनमात्र में रखा गया है, मूल वेतन, नए निबंधनों के अधीन वेतनमात्र में उसके रखे जाने की तारीख से अनुसूची "छ" में यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमात्र में, तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।
- (3) प्रत्येक विकास अधिकारी, जिसका मूल वेतन उप-पैरा (1) या उप-पैरा (2) के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमात्र में नियत किया गया है, पुनरीक्षित निबंधनों और नए निबंधनों के बीच सकल परिलिंगियों में अन्वयन, अन्वयन राहत और तकनीकी अहंताओं के लिए भना (अधिक्षय निधि में विकास अधिकारी के अनिवार्य अधिदाय की कटौती करने के पश्चात्) । जनवरी, 1987 में प्रारंभ होने वाली अवधि या नए निबंधनों के अधीन वेतनमात्र में उसके रखे जाने की तारीख से, जो भी पश्चात्-वर्ती हो, प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए संवत्सर उप-पैरा (1) के अनुवातम वेतनमात्र में नियत किया जाएगा ।
- (4) प्रत्येक विकास अधिकारी का, जो 1 जनवरी, 1987 को परिवीक्षा पर है और जिसकी संशोधन स्कीम, 1987 के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात्, विकास अधिकारी ग्रेड I में पुष्टि की गई है, मूल वेतन उसकी पुष्टि की तारीख से, विकास अधिकारी ग्रेड I के अनुवातम वेतनमात्र में नियत किया जाएगा ।

२व. साम्यापूर्ण अनुतोष और उसका समायोजन :—

- (1) प्रत्येक विकास अधिकारी की वाबत जिसका खर्च अनुपात, वर्ष 1983, 1984 और 1985 के लिए उक्त स्कीम के अधीन अनुबंधित सीमाओं के भीतर था, अनुसूची छ के अनुसार मूल वेतन 1 जनवरी 1984 को या नये निबंधनों के अधीन वेतनमात्र में रखे जाने की तारीख से, उनमें से जो भी पश्चात्-वर्ती हो, उप-पैरा (4) में यथा उपबंधित साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में वर्ष 1984, 1985 और 1986 के लिए संदर्भ किया जाएगा ।
- (2) विकास अधिकारी की वाबत, जिसका खर्च अनुपात वर्ष 1983, 1984, 1985 में से किन्हीं दो वर्षों के लिए उक्त स्कीम के अधीन अनुबंधित सीमाओं के भीतर था, मूल वेतन अनुसूची छ के अनुसार 1 जनवरी, 1985 को या नये निबंधनों के अधीन वेतनमात्र में रखे जाने की तारीख को इनमें से जो भी पश्चात्-वर्ती हो, नियत किया जाएगा और उसे वर्ष 1985 और 1986 के लिए उप-पैरा (4) में यथा उपबंधित साम्यापूर्ण अनुतोष संदर्भ किया जाएगा ।
- (3) विकास अधिकारी की वाबत जिसका खर्च अनुपात वर्ष 1983, 1984 और 1985 में से किसी एक वर्ष के लिए उक्त स्कीम के अधीन अनुबंधित सीमाओं के भीतर था, मूल वेतन अनुसूची छ के अनुसार एक जनवरी, 1986 को या नये निबंधनों के अधीन वेतनमात्र में रखे जाने की तारीख को, इनमें से जो भी पश्चात्-वर्ती हो, नियत किया जाएगा और उसे वर्ष 1986 के लिए उप-पैरा (4) में यथा उपबंधित साम्यापूर्ण अनुतोष संदर्भ किया जाएगा ।

(4) इस पैरा के अधीन साम्यापूर्ण अनुतोष के संदाय का छाँग और रोति वह द्वारा जो नियम के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाए :

परन्तु ऐसे विकास अधिकारियों की दशा में जिनका खर्च अनुपात एक या अधिक वर्षों में, अर्थात् 1983, 1984, 1985 या 1986 में अनुबंधित सीमाओं से प्रधिक हो जाता है, कौपिक आगामी वर्षों में ऐसे विकास अधिकारियों को संदर्भ बात भना, उक्त स्कीम के पैरा 11 के उप-पैरा (2) में उपबंधित रूप में काट लिया जाएगा और उप-पैरा (1), (2) या (3) में यथा उपबंधित फर्नीचर (फिटमेट) और साम्यापूर्ण अनुतोष यदि कोई हो, तभी लागू किया जाएगा जब बात भने की ऐसी कटौती, जैसा आवश्यक हो, प्रभावी कर दी जाती है :

परन्तु यह और भी कि ऐसे विकास अधिकारियों की दशा में जिन्हें कोई साम्यापूर्ण अनुतोष मद्देप नहीं है या जहाँ संदेय साम्यापूर्ण अनुतोष कटौती की रकम से कम है, वहाँ सम्बद्ध विकास अधिकारी को संदेय परिलिंगियों में से, 1 जनवरी, 1987 के पश्चात् ऐसी रीति में वसूल की जाएगी जैसी नियम के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "साम्यापूर्ण अनुतोष" में नये निबंधनों और पुनरीक्षित निबंधनों के अधीन सकल परिलिंगिया, अतिरिक्त राहत और भविष्य निधि के संकलन के बीच का अन्तर अभिप्रेत है ।

(4) विकास अधिकारी को अनुबंत साम्यापूर्ण अनुतोष इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से उसके खर्चों में जोड़ दिया जाएगा और उसका खर्च अनुपात तदनुसार संगणित किया जाएगा :—

(क) पहले वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष का 50% खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा ।

(ख) पहले वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष धन दूसरे वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष का 50% कार्य निष्पादन वर्ष 1987 के खर्च में जोड़ा जाएगा ।

(ग) दूसरे वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष का 65% कार्य निष्पादन वर्ष 1988 के खर्च में जोड़ा जाएगा ।

(घ) दूसरे के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष का 25% और तीसरे वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष का 40% कार्य निष्पादन वर्ष 1989 के खर्च में जोड़ा जाएगा ।

(ज) तीसरे वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण का 60% कार्य निष्पादन वर्ष 1990 के खर्च में जोड़ा जाएगा ।

#### स्पष्टीकरण :

इस उप-पैरा के प्रयोजन के लिए "पात्रता वर्ष" से 1984, 1985 या 1986 वर्ष अभिप्रेत होगा, जिसके लिए साम्यापूर्ण अनुतोष अनुतोष है और जहाँ 1984, 1985 और 1986 के सभी वर्षों के लिए साम्यापूर्ण अनुतोष का संदाय किया गया है वहाँ पहला, दूसरा और तीसरा पात्र वर्ष क्रमशः 1984, 1985 और 1986 होंगे । जहाँ साम्यापूर्ण अनुतोष का कार्य निष्पादन वर्ष 1985 और 1986 होगा । जहाँ साम्यापूर्ण अनुतोष का संदाय क्रमशः एक वर्ष, 1986 के लिए किया गया है, वहाँ पहला और दूसरा वर्ष क्रमशः 1985 और 1986 होगा । जहाँ साम्यापूर्ण अनुतोष का संदाय क्रमशः एक वर्ष, 1984 के लिए किया गया है, वहाँ इसमें पहला पात्र वर्ष समझा जाएगा ।

7. शोध्यों का संदाय—ऐसे विकास अधिकारी जो 1 जनवरी, 1984 को या उसके पश्चात् बेवानियत हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिन्होंने न्यायपत्र के दिया है, जो वर्ष 1 अधिकारी के रूप में प्रोक्षण हो गए हैं या जो लिपिकीय कर्मचारित्व के रूप में संपरिवर्तन हो गए हैं, यथास्थिति उनकी सेवानियुक्ति, मरण, स्थानपत्र, प्रोक्षणित या संपरिवर्तन की तारीख तक उपराख्ययों का अन्तर, साम्यापूर्ण अनुतोष और उपवान का अन्तर, यदि कोई हो, पैरा 7-क और 7ब के अनुसार संदाय किया जाएगा ।

परन्तु उपलब्धियों के शोधों और साम्यापूर्ण अनुतोष का संदेश याद्य भस्ते के, यदि कोई हो, आधिकारी की वसूली के अधीन रहते हुए निया जाएगा।

4. उक्त स्कीम के पैरा 11 के स्थान पर निम्ननिवित पंरा रखा जाएगा, यथार्थ :-

**"11. खर्च नियन्त्रण—"**

- (1) प्रयोक विकास अधिकारी ऐसे खर्च से कार्य करेगा जिससे कि वह पैरा 3 के खंड (17) के उपचंड (ग) में अनुबंधित सीमाओं के भीतर अपना खर्च अनुपात बनाए रख सके।
- (2) यदि किसी विणिष्ट कार्य निष्पादन वर्ष की बाबत किसी विकास अधिकारी के संबंध में खर्च अनुपात अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो जाता है, तो आगामी कार्य निष्पादन वर्ष में उसको संवेद बाह्य भस्ता उम रकम तक कम कर दिया जाएगा, जिस तक उसका खर्च अनुपात अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो गया है।
- (3) यदि किसी विकास अधिकारी की बाबत, खर्च अनुपात लगातार दूसरे कार्य निष्पादन वर्ष के लिए अनुबंधित सीमा से अधिक हो जाता है, तो उसे जेतावनी का पत्र जारी किया जाएगा कि यदि उसका खर्च अनुपात लगातार तीसरे या पछातवर्ती कार्य निष्पादन वर्षों के लिए अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो जाता है, तो उसका खर्च अनुपात लगातार तीसरे या पछातवर्ती कार्य निष्पादन वर्षों के लिए अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो जाता है, तो उसको आगामी कार्य निष्पादन वर्ष में संदेश (नान-फोर) बाह्य भत्ता कम किए जाने के लिए नहीं है, तो वह मूल वेतन में कमी के लिए बाह्य भत्ता, जैसाकि उप-पैरा (4) के नीचे सारणी में उपलब्धित है।
- (4) यदि किसी विकास अधिकारी की बाबत खर्च अनुपात लगातार तीसरे या पछातवर्ती कार्य निष्पादन वर्षों के लिए अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो जाता है, तो उसको आगामी कार्य निष्पादन वर्ष में संदेश (नान-फोर) बाह्य भत्ता, यदि कोई हो, उस रकम तक कम कर दिया जाएगा, जिस तक उसका खर्च अनुपात अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो गया है।

परन्तु यदि उसको कोई (नान-फोर) बाह्य भत्ता संदेश नहीं है या ऐसे तीसरे या पछातवर्ती लगातार कार्य निष्पादन वर्षों के आगामी वर्ष में उसको संवेद बाह्य भत्ता की रकम अधिक खर्च से कम है, तो कमियों को खर्च की अनुबंधित सीमाओं के अनुसूच करने के लिए ऐसे विकास अधिकारी को अवमर देने के लिए सुझाव अंकन वर्ष की पहली जनवरी से नीचे दी गई सारणी के अनुपात प्रभावी किया जाएगा।

**सारणी**

मूल वेतन में कमी करना, जहाँ खर्च अनुपात सुझाव अंकन वर्ष में अनुबंधित सीमाओं से अधिक है।

अनुबंधित सीमाओं पहले लगातार लगातार लगातार लगातार सं.	के ऊपर वास्तविक अवमर दूसरे अव- तीसरे चौथे 5वें और छागत अनुपात पर सर पर अवमर अवमर पश्चातवर्ती पर पर अवमर पर
--	--

सुझाव अंकन वर्ष को पहली जनवरी से प्रभावी को जाने वाली कमियों की संख्या

1. 1% से अधिक नहीं	1	1	1	1	1
2. 1% से थोड़ा अधिक किन्तु 3% से अधिक नहीं	1	1	2	2	2
3. 3% से थोड़ा अधिक किन्तु 5% से अधिक नहीं	2	2	3	3	1
4. 5% से थोड़ा अधिक	2	3	3	4	4

**टिप्पण 1.** यदि कोई विकास अधिकारी, विकास अधिकारी प्रेड-1 के वेतनमान में है, और ऊपर यथा उपबंधित कटौती द्वारा उम का मूल वेतन, वेतनमान के न्यूनतम से कम हो जाता है, तो उम का मूल वेतन, विकास अधिकारी प्रेड-1 के वेतनमान के अधिकतम से एक प्रक्रम पर, नियन्त्रित किया जाएगा। यदि उक्त विकास अधिकारी, विकास अधिकारी प्रेड-1 के वेतनमान में रखे जाने के पश्चात भी अनुबंधित खर्च सीमाओं के पर कार्य करना जारी रखता है, तो मूल वेतन में कटौती, उतने प्रक्रमों की संख्या तक, जो भुजंगम उत्तरवर्ती अवमर को लागू है, विकास अधिकारी प्रेड-1 में वेतनमान में शारम्भ होगी।

**टिप्पण 2.** यदि ऐसी कटौती के पश्चात मूल वेतन विकास अधिकारी प्रेड-1 के वेतनमान के न्यूनतम से कम हो जाता है, तो ऐसे विकास अधिकारी का मूल वेतन, विकास अधिकारी प्रेड-1 के वेतनमान के न्यूनतम पर नियन्त्रित किया जाएगा।

**(5)** उम विकास अधिकारी को जिसका मूल वेतन उप पैरा (4) के अधीन कटौती के पश्चात विकास अधिकारी प्रेड-1 के वेतनमान के न्यूनतम पर नियन्त्रित किया गया है, अनुबंधित खर्च सीमाओं के अनुसूच करने के लिए एक वर्ष का अवमर दिया जाएगा और जेतावनी दी जाएगी कि उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, यदि वह वह भी अनुबंधित खर्च सीमाओं से अधिक हो जाता है।

**(6)** यदि विकास अधिकारी, विकास अधिकारी प्रेड-1 के वेतनमान के न्यूनतम मूल वेतन से कम के शूरू उपरोक्त (5) के अधीन एक वर्ष का अवमर देने के पश्चात भी अनुबंधित खर्च सीमाओं के पर बना रहता जारी रखता है तो उसकी सेवाएं उसको 30 दिन की सूचना देने के पश्चात् किसी अधिकारी द्वारा जो सज्जान मात्रविनापन के विकास अधिकारी को जाने के नहीं हैं, समाप्त की जाएगी :

परन्तु किसी भी विकास अधिकारी की सेवाएं तब तक समाप्त नहीं की जाएंगी, जब तक कि उसे मेंा समाप्त करने वाली सूचना की तामील करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उप पैरा (7) प्रवीन इस प्रयोगन के लिए गठित अपील समिति को अपील करने का अवमर प्रदान नहीं किया जाता है शारीर जब तक उक्त अपील समिति उक्त अपील पर विचार नहीं कर लेती है और उसे पुष्ट नहीं करती है कि संवित्रित विकास अधिकारी को सेवाएं समाप्त किए जाने के दायित्वाधीन हैं।

परन्तु और भी कि संबंधित विकास अधिकारी की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी, यदि अपील समिति उस को अपील पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय करती है कि उसको कुछ अनुपोष किया जाना चाहिए।

**(7)** उप पैरा (6) में निर्दिष्ट अपील समिति इस पैरा के अधीन सेवा की समाप्ति के लिए दायी विकास अधिकारी को अनुपोष देने के लिए समय-ममत पर नियम के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और उक्त रामिति सुझाव अंकन कोर्टों की प्रीमियर वर्ष, खर्च अनुपात की संगणना में वास्तविक अवमरताओं, रूपाली, द्विटना या ऐसी अविनियम परिशमनकारी परिस्थितियां, जो विकास अधिकारी के नियंत्रण के पर हों, और जो करवार उपायों को प्रतिकूलतः प्रभावित करती हों, ध्यान में रखते हुए, अपील पर विचार करेंगी और उप पैरा (8) में उपबंधित उम अनुतोष से भिन्न उतने अनुतोष का उपवर्ध्य करेंगी जो प्रध्येन पासक में घावालक समझा जाए।

**(8)** कोई भी विकास अधिकारी जिसकी नियम पैरा 3 पैरा के अधीन समाप्त भी जा सकती है उसके विनिदिष्ट अनुरूप पर, ऐसे विवरणों पर, जो नियम के अध्यक्ष द्वारा विनियमित गत वर्ष लियार्थीकृत समझा जाएगा कि-

(i) वह कम से कम 45 वर्ष का है किन्तु उसने 55 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और उसने विकास अधिकारी के रूप में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की है, या

(ii) अविशिष्ट परिसमानकारी परिस्थितियों के, जैसे कि क्रमण, अति या निःशक्तता के आधार है।

(9) जहाँ किसी विकास अधिकारी के बाह्य (नानकोर) भने, की कटीती उप पैरा (2) या उप पैरा (3) के अधीन की जाती है या उप पैरा (4) के अधीन किसी प्रबलों की जाती है या उप पैरा (6) के अधीन उसकी सेवाएँ समाप्त की जाती हैं वहाँ पैसे वाप्त (नानकोर) भने की कटीती या कमियाँ या सेवाओं की समाप्ति, जारी नहीं भवनी जाएगी।

5. उक्त स्कीम के पैरा 12 में—

(I) उप पैरा (1) में खंड (10) का लोप किया जाएगा,

(2) उप पैरा (i) के पश्चात निम्नलिखित उग पैरा अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

(1क) निगम का अध्यक्ष समय पर कुछ बीमा की ज्ञात या अविकसित किसी का विकास करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उप पैरा (i) में दूसरीबार कारबाह की किसी से परिवर्तन या समोद्देश कर सकेगा। निगम का अध्यक्ष शामिल या किन्तु अन्य विनियोगी बीमों के बगाँ के विकास के लिए विविध प्रोत्साहन की स्कीम के लिए भी उपबन्ध कर सकेगा, यदि प्रावधारक समझ जाए और उस रीति में जो उसके द्वारा विनियित की जाए।<sup>4</sup>

6. उक्त स्कीम के पैरा 13 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्—

“13. बेतन बुद्धि—वह विकास अधिकारी जिसका सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के लिए खर्च अनुपात पैरा 3 के खंड (17) के उपबंड (g) में अनुबंधित सीमाओं से अधिक नहीं है, सुसंगत अंकन वर्ष की पहली जनवरी का सुसंगत पुनरीजित बेतनमान ने बेतनबद्धि अंजित करेगा, परन्तु यह तब उसने उक्त अंकन वर्ष की जनवरी के मास में बेतनमान में, 12 मास की सेवा पूरी कर ली हो।”

परन्तु उस विकास अधिकारी के मामले में, जिसका सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के लिये खर्च अनुपात अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो जाता है, बेतन बुद्धि विये जाने के लिये, अनुसूचित प्रीमियम आय के संकलन पर और सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष तथा दीक पूर्वसंसीद्धि वर्षों के लिये सकलित लागत पर मंगणित श्रीमन खर्च अनुपात के आधार पर, विचार किया जा सकता है।

7. उक्त स्कीम के पैरा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात्—

“14. लागत पर प्रावधारित बुद्धि प्रोत्साहन.—उस विकास अधिकारी को जिसका किसी कार्य सांचादन वर्ष के लिये खर्च अनुपात पैरा 3 के खंड (17) के उपबंड (g) में अनुबंधित लागत सीमा से अधिक है और उसने उक्त कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान कम से कम 3,00,000 रुपये की अनुसूचित प्रीमियम आय उपाल भी है और उक्त कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान पूर्व कार्य निष्पादन वर्ष में अनुसूचित प्रीमियम आय में 60,000 रुपये की अनुनाम बुद्धि की है।

अंकन वर्ष 1988 में पूर्वदर्ता कार्य निष्पादन वर्ष का अनुसूचित आय के उन पर कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान अनुसूचित प्रीमियम अन्य के बुद्धि को दूषा करने के प्रतिवार्ता रकम के बगायर लागत-प्रावधारित बुद्धि प्रोत्साहन या समाय, प्रावधारित खर्च अनुपात और उस विकास अधिकारी के वाग्विक खर्च के अनुपात के बीच अन्तर का सदाय किया जायेगा।

परन्तु यह कि अनुबंधित लागत के अनुपात और वास्तविक लागत के अनुपात के बीच अधिकतम अंतर की लागत पर प्राप्तार्थी प्रोत्साहन बुद्धि की संगति नहीं करने के लिये लिया जाये तो 5% में अधिक नहीं होगा।

परन्तु यह और कि लागत पर प्राप्तार्थी बुद्धि प्रोत्साहन की रहन संबंधित विकास अधिकारी द्वारा सुमाना कार्य निष्पादन वर्ष के द्वारा लिये गये बाहर मास के मूल बेतन से अधिक नहीं जाती।”

8. उक्त स्कीम के पैरा 15 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात्—

“15. लाभ प्रोत्साहन—ऐसा कोई विकास अधिकारी जिसका सुमाना कार्य निष्पादन वर्ष के लिये लाभ अनुपात पैरा 3 के खंड (17) के उपबंड (g) में अनुबंधित सीमा के भीतर है और उक्त कार्य निष्पादन वर्ष के लिये जिसकी अनुसूचित प्रीमियम आय, गृह कार्य निष्पादन वर्ष में कम नहीं है, नीचे के मार्गों में विविध खर्चों पर प्राप्त प्रोत्साहन प्रत्युदात विये जाने के लिये विचार किये जाने का पात्र होगा।

#### मार्गी

#### प्रचालन प्रधिष्ठेय

लाभ प्रोत्साहन के रूप में अनुदात किये जाने वाले प्रधालन प्रधिष्ठेय की प्रतिशतता

#### 20 प्रतिशत से कम

खंड	20 प्रतिशत या उससे अधिक कितु 22.5 प्रतिशत से कम	1. 25 प्रतिशत
22.5 प्रतिशत या उससे अधिक कितु 26 प्रतिशत से कम	2. 5 प्रतिशत	
26 प्रतिशत या उससे अधिक कितु 27 प्रतिशत से कम	3. 5 प्रतिशत	
27 प्रतिशत या उससे अधिक कितु 28 प्रतिशत से कम	4. 5 प्रतिशत	
28 प्रतिशत या उससे अधिक कितु 29 प्रतिशत से कम	5. 5 प्रतिशत	
29 प्रतिशत या उससे अधिक कितु 30 प्रतिशत से कम	6. 5 प्रतिशत	
30 प्रतिशत या उससे अधिक कितु 31 प्रतिशत से कम	7. 5 प्रतिशत	

परन्तु यह कि उस पैरा के अधीन लाभ प्रोत्साहन किसी विकास अधिकारी की अंकन वर्ष 1988 से संदेय होगा और यह उसके द्वारा सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के द्वारा लिये गये वार्षिक मूल बेतन से अधिक नहीं होगा और उसकी लागत, जिसके अन्तर्गत लाभ प्रोत्साहन और लागत पर आधारित बुद्धि प्रोत्साहन यदि कोई हो, भी है, पैरा 3 के खंड (17) के उपबंड (g) में अनुबंधित सीमा के भावार है।”

9. उक्त स्कीम के पैरा 16 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात्—

“16. भविष्य निधि—प्रत्येक विकास अधिकारी, भविष्य निधि में अपने मूल बेतन के 8-1/3 प्रतिशत को दर में अनिवार्य करेगा और यथास्थिति, निगम या कंपनी भी मास प्रतिशत करेगा।”

10. उक्त स्कीम के पैरा 17 में, उपपैरा (1) के खंड (x) के प्रत्येक कितु परस्पर से पहले, निम्नलिखित खंड अंत स्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

“(खंड) उपदान की अनुकूलता के लिये अंकन भवा में भविष्य खंड (x) और खंड (y) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक विकास अभ्यन्तरिक्ष को जिसके निधि या कंपनी या दिनों में 15 वर्ष में अन्यून निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके छह मास से अधिक के भाग के लिये, 30 वर्ष की सेवा तक अधिकारी 15 मास के अधीन रहने हुए प्रकार मास के मूल बेतन की दर पर



(2) उक्तमध (i) में किसी दाता के होने हुए भी, ऐसा विकास अधिकारी जो नागरिक 31-12-1986 को ३० रु. प्रतिमास नगर प्रतिकर भत्ते के स्वरूप में प्राप्त कर रहा है और मंजूरीदान स्कोर्स, 1987 के प्रधीन नगर प्रतिकर भत्ते का पात्र नहीं रहा है, उक्त रकम नव तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उसी स्थान पर तैनात रहता है।

#### V. पर्वतीय स्थान भत्ता :—

विकास अधिकारियों को संदेश पर्वतीय स्थान भत्ते के भाष्मान निष्ठलिखित होने :—

(1)

(2)

(i) औसत समुद्र तल से 1500 मूल बेतन के इस प्रतिशत की दर मीटर तथा उससे अधिक की में किसी प्रतिमास 100 रु. के ऊंचाई पर स्थित स्थान पर तैनात प्रधीन रहते हुए।

(ii) मरकरा और ऐसे स्थानों पर, जिन्हे केवलीय मरकरा/राज्य मरकराओं ने अपने कर्मचारियों के लिए विनियोजित स्वरूप में "पर्वतीय स्थान" घोषित किया है में औसत समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक किस्ति 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात।

#### VI. तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता :

ऐसा विकास अधिकारी जिसकी पुष्टि की जा चुकी है और जो नीचे उल्लिखित किसी परीक्षा में अर्हता होता है या जिसने अर्हता प्राप्त की है, जो परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख में या पुष्टि की तारीख से या 1-1-1987 से जो, जो भी नागरिक आद में हो, नीचे उल्लिखित तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता दिया जाएगा :—

परीक्षा प्रहृता भत्ता प्रतिमास

(1)

(2)

वीमा संस्थानों का परिसंच या चार्टर्ड वीमा संस्थान

(i) लाइसेंसिंग 40 रुपए

(ii) एसोसिएटशिप पूरा करने वाला 50 रुपए

(iii) फैलोशिप पूरी करने पर 130 रुपए

वीमानक संस्थान लंदन

(i) कोई नीत विषय 100 रुपए

(ii) कोई छः विषय 130 रुपए

चार्टर्ड एकाउंटेंट मंस्यान या नागर और मंकर्म सेल्वाकार संस्थान :—

(i) इंटरमिडिएट पूरा करने पर 80 रुपए

(ii) अंतिम ग्रुप 'क' 100 रुपए

(iii) अंतिम ग्रुप 'ब' 130 रुपए

परन्तु यह कि, एक से अधिक अर्हक भत्ता अनुशेष नहीं होगा।

कर्मी घट्टाभों के लिए भग द्वारा जाने से संबंधित विकास अधिकारी को जीवन तथा पर कोई भत्ता नहीं पड़ेगा। जहाँ विकास अधिकारी को उक्त किसी परीक्षा में अर्हता होने के लिए पढ़ने ही कोई अंतिम वृद्धि या कोई अन्य आश्री अधिकारी अधिकारी को विद्या दिया गया है, वहाँ वहाँ से प्राप्त फायदे की मात्रा पर नियंत्रण करने हुए अर्हता भत्ते की रकम में, यथोचित स्वरूप से कमी कर दो जानी या वह अनुशेष नहीं होगा।

मन्त्रमुखी व्य

(पैग 7-क और 7-ब देखिए)

मूल बेतन के नियन्त्रण के लिए तत्पात्री प्रक्रमों का आर्द्ध

विकास अधिकारी ग्रेड—I विकास अधिकारी ग्रेड-II

विकास भत्ता मूल बेतन (रुपए)	पुनर्गठित मूल बेतन (रुपए)	विकास भत्ता मूल बेतन (रुपए)	पुनर्गठित मूल बेतन (रुपए)
1	2	3	4
250	720	175	550
265	780	185	580
280	840	195	610
295	900	205	640
315	960	215	670
335	1020	225	700
355	1080	240	730
375	1150		
400	1220		
425	1290		
450	1360		
475	1430		
500	1500		
525	1580		
555	1660		
585	1740		
615	1820		
645	1900		
675	1980		
710	2060		
745	2140		
780	2220		
815	2300		
850	2380		

[पात्रन म. 114(2)/व्य. IV/87]

ए. के. पांड्या, अपर मणिव (इंडियोर्स)

MINISTRY OF FINANCE  
 (Department of Economic Affairs)  
 NOTIFICATION  
 New Delhi, the 13th February, 1987  
 INSURANCE

S.O. 80(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976, namely :

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1987.

(3) It shall apply to all Development Officers who are in the whole time employment of the Company on the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 1987 (hereinafter referred to as the Amendment Scheme, 1987) and who are appointed as such after such commencement.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3 :—

(1) after clause (1) the following clause shall be inserted, namely :—

(1A) "appraisal year" means the calender year during which performance appraisal of Development Officer is done and shall be the calender year following the performance year ;

(2) for clause (2), the following clause shall be substituted, namely :—

(2) "basic pay" means the pay admissible from time to time to the Development Officers in the scale of pay set out in the Schedule A appended to this Scheme ;

(3) for clause (5), the following clause shall be substituted, namely :—

(5) "Company" means the National Insurance Company Limited, the New India Assurance Co. Ltd., the Oriental Insurance Company Limited or the United India Insurance Company Limited;

(4) for clauses (7) and (8) the following Clauses shall be substituted, namely :—

(7) "cost" means the cost incurred on a Development Officer for procuring general insurance business during a performance year and includes, in addition to the gross emoluments of such Development Officer, allowance for technical qualifications, non-core allowances, expenses on vehicle and telephone, bonus or ex-gratia payment, travelling expenses on tours undertaken for procuring general insurance business, paid to the Development Officer during that year but does not include employer's contribution to Provident Fund;

(8) "cost ratio" in respect of a performance year means the ratio expressed as percentage of the cost incurred on a Development Officer to the scheduled premium income procured through him;

(5) after clause (9), the following clause shall be inserted, namely :—

(9A) "Development Officer" means members of the Development Staff, who immediately before the commencement of the Amendment Scheme, 1987 were categorised or appointed as Inspector Grade-I and Inspector Grade-II and on such commencement designated, respectively, as Development Officer Grade-I and Development Officer Grade-II."

(6) in clause (11)—

(i) the words "payable under the new terms" shall be omitted ;

(7) for clause (14), the following clause shall be substituted, namely—

(14) "operating surplus" means the surplus, if any, after deducting the outgo from the income procur ed through the Development Officer and for the purpose of determining operating surplus—

(a) income shall consist of—

(i) in reserve for unexpired risk calculated at the rate of 50 per cent of the scheduled premium income of the previous performance year; and

(ii) the scheduled premium income of the performance year; and

(b) the out-go shall consist of the aggregate of the following items for the relevant performance year,—

(i) incurred claims, calculated by adding the amount of claims paid during the year, to the amount of claims outstanding at the end of the year and deducting therefrom the provision of claims outstanding at the end of the previous performance year.'

**Explanation :—**In this item,—

(a) Claim in excess of one lakh of rupees arising from any single claim shall be limited to one lakh of rupees;

(b) Claims in respect of any business excluded from the scheduled premium income shall not be taken into account while calculating incurred claims.

(ii) ten per cent of the scheduled premium income towards administrative expenses;

(iii) cost incurred on Development Officer;

(iv) the commission paid or payable on the scheduled premium income.

(v) reserve for unexpired risk at the end of the year at the rate of 50 per cent of the scheduled premium income.

(14A) "performance year" means the calender year in respect of which the performance appraisal is considered ;

(8) after clause (15A), the following clauses shall be inserted, namely :—

(15-B) "revised terms" means the revised scales of pay and allowances as specified in Schedule A ;

(15C) "revised scales of pay" means the revised scales of pay specified in Schedule A ;

(9) in clause (17), after the Explanation, the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(c) in relation to cost ratio from the performance year commencing on the 1st January, 1987, the ratio specified in column (2) of the Table below

and incurred on a Development Officer specified in the corresponding entry in column (1) thereof :—

TABLE

Development Officer Operating at	Cost Ratio	
	(1)	(2)
Applicable in relation to paragraphs 11 and 13	Applicable in relation to paragraphs other than 11 and 13	Applicable in relation to paragraphs 11 and 13
(A) cities with population exceeding 12 lakhs and urban agglomeration of Panaji and Marmugoa	8%	7%
(B) Cities with population of 5 lakhs and above, but not exceeding 12 State Capital with population not exceeding 12 lakhs and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair	9%	8%
(C) Other Centres	11%	10%

Provided that : (a) for the performance years 1987, 1988 and 1989 relaxation of 1.5 per cent, 1.5 per cent and 1 per cent, respectively, shall be allowed in the Stipulated Limits of cost ratios specified in the Table.

(b) in respect of premium obtained directly by Development Officer without intervention of an agent, relaxation of 1 per cent in cost will be allowed for application of provisions of paragraphs 11 and 13."

3. After paragraph 7 of the said Scheme, the following paragraphs shall be inserted, namely :— "7A. Fixation of basic pay in the revised scales of pay :—

- (1) The basic pay of every Development Officer who has been placed in the scale of pay under the new terms as on the 31st December, 1986 shall be fixed at a corresponding stage in the relevant revised scale of pay with effect from the 1st January, 1987 as specified in Schedule B.
- (2) The basic pay of every Development Officer who has been placed under the scale of pay under the new terms on or after the 1st January, 1987 but before the publication of the Amendment Scheme, 1987 in the Official Gazette, shall be fixed at the corresponding stage in the relevant revised scale of pay as specified in the Schedule "B" with effect from the date of his placement in the scale of pay under new terms.
- (3) Every Development Officer whose basic pay is fixed in the revised scale of pay in accordance with the sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2), shall be paid for the period commencing from 1st day of January 1987 or the date of his placement in the scale under the new terms, whichever is later, the difference of gross emoluments, interim relief, and allowance for technical qualification (after deducting the Development Officer's compulsory contribution to the Provident Fund) between the revised terms and the new terms.
- (4) The basic pay of every Development Officer who is on probation on the 1st day of January, 1987 and confirmed as Development Officer Grade I after publication of the Amendment Scheme, 1987 in the Official Gazette shall be fixed at the minimum of the scale of Development Officer Grade I from the date of his confirmation.

#### 7B Equitable relief and its adjustment :—

- (1) In respect of every Development Officer whose cost ratio was within the stipulated limits under the said Scheme for the years 1983, 1984 and 1985, basic pay shall be fixed as on the 1st January, 1984 or the date of placement in the scale under the new terms, whichever is later, as per Schedule B and shall be paid for the years 1984, 1985 and 1986 an equitable relief as provided in sub-paragraph (4).
- (2) In respect of Development Officer whose cost ratio was within the stipulated limits under the said scheme for any two years out of the years 1983, 1984 and 1985, basic pay shall be fixed as on the 1st January, 1985 or the date of placement in the scale under the new terms, whichever is later, as per Schedule B and shall be paid for the years 1985 and 1986 an equitable relief as provided in sub-paragraph (4).
- (3) In respect of Development Officer whose cost ratio was within the stipulated limits under the said scheme for any one year out of the years 1983, 1984 and 1985, basic pay shall be fixed as on 1st January, 1986 or the date of placement in the scale under the new terms, whichever is later, as per Schedule B and shall be paid for the year 1986 equitable relief as provided in sub-paragraph (4).
- (4) The mode and manner of payment of equitable relief under this paragraph shall be as decided by the Chairman of the Corporation.

Provided that in case of Development Officers whose cost ratio exceeded stipulated limits in one or more years, viz. 1983, 1984, 1985 or 1986, the non-core allowance paid to such Development Officers in the respective following years shall be reduced as provided in sub-paragraph (2) of paragraph 11 of the said Scheme and fixation and payment of equitable relief, if any as provided in sub-paragraph (1), (2) or (3) shall be effected only after such reduction of non-core allowance, as may be necessary, is effected :

Provided, further that in case of Development Officers to whom no equitable relief is payable or where the equitable relief payable is less than the amount of reduction recovery shall be effected from the emoluments payable to the concerned Development Officer after the 1st January, 1987 in

the manner as may be decided by the Chairman of the Corporation.

**Explanation.**—For the purposes of this paragraph “equitable relief” means the difference between the aggregate of the gross emoluments, interim relief and provident fund under the new terms and the revised terms.

(4) The equitable relief granted to a Development Officer shall be added to his cost in the manner hereinafter provided and his cost ratio shall be accordingly computed:—

- (a) 50 per cent of the eligible first year's equitable relief shall not be added to the cost.
- (b) 50 per cent of the eligible first year's equitable relief plus 10 per cent of the eligible second year's equitable relief shall be added to the cost of performance year 1987.
- (c) 65 per cent of the eligible second year's equitable relief shall be added to the cost of the performance year 1988.
- (d) 25 per cent of the eligible second year's equitable relief and 40 per cent of the eligible third year's equitable relief shall be added to the cost of performance year 1989.
- (e) 60 per cent of the eligible third year's equitable relief shall be added to the cost of the performance year 1990.

**Explanation.**—For the purpose of this sub-paragraph, “eligible years” shall mean the year 1984, 1985, or 1986 for which equitable relief is admissible and where equitable relief is paid for all the years 1984, 1985 and 1986, the eligible first, second and third years shall be 1984, 1985 and 1986 respectively. Where equitable relief is paid only for the years 1985 and 1986, the eligible first and second year shall be 1985 and 1986 respectively. Where equitable relief is paid only for one year viz., 1986 it shall be deemed to be the eligible first year.

**7C. Payment of dues.**—The Development Officers who have retired, died, resigned, promoted as class I officers or converted as clerical staff, on or after the 1st day of January, 1984 shall be paid up to the date of their retirement, death, resignation, promotion or conversion, as the case may be, the difference in emoluments, equitable relief and the difference in gratuity, if any, as per paragraphs 7A and 7B:

Provided that the payment of dues in emoluments and equitable relief shall be subject to recovery of excess non-core allowance, if any.

4. For paragraph 11 of the said Scheme the following paragraph shall be substituted namely:—

#### “11. Cost Control—

(1) Every Development Officer shall work with such cost as to maintain his cost ratio within the limits stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3.

(2) If the cost ratio in respect of a Development Officer for a particular performance year exceeds the stipulated limits, the non-core allowance payable to him in the following performance year shall be reduced to the extent of the amount by which his cost ratio exceeded the stipulated limits.

(3) If in respect of a Development Officer, cost ratio is in excess of stipulated limit for second performance year in succession, he may be issued a letter of warning that in events of his cost ratio exceeding stipulated limits for third or subsequent performance years in succession, his non-core allowance shall continue to be reduced in the following years to the extent necessary to bring his cost ratio within stipulated limits and, if there are no non-core allowance to be reduced, he shall be liable to decrements in basic pay as indicated in the Table below sub-paragraph (4).

(4) If in respect of a Development Officer cost ratio is in excess of stipulated limit for the third or subsequent performance years in succession, the non-core allowance payable to him if any, in the following performance year shall be reduced to the extent of the amount by which his cost ratio exceeded the stipulated limits :

Provided that if no non-core allowance are payable to him or the amount of non-core allowance payable to him in the year following such third or subsequent successive performance years is less than the excess cost, decrements shall be effected to such Development Officer as per table below from the 1st January of the relevant appraisal year to provide him an opportunity to conform to the stipulated limits of cost.

TABLE  
Reduction in Basic pay where cost ratio is in excess of stipulated limits in the Relevant Performance year

St. Actual cost No.	On 1st	On 2nd	On 3rd	On 4th	On 5th and subse- quent
Ratio over stipulated limits	Occasion	Successive occasion	Successive occasion	Successive occasion	Successive occasi. (s)
<b>Number of Decrements to be effected from 1st January of Relevant Appraisal year.</b>					
1. By not more than 1%	1	1	1	1	1
2. By margin exceeding 1% but not exceed- ing 3%	1	1	2	2	2
3. By margin exceeding 3% but not exceeding 5%	2	2	3	3	4
4. By margin exceeding 5%	2	3	3	4	4

**NOTE I.**—If a Development Officer is in the scale of Development Officer Grade I, and by reduction as provided above, his basic pay falls below the minimum of the scale, his basic pay shall be fixed at one stage below the maximum of the scale of Development Officer Grade II. If the

said Development Officer continues to operate beyond stipulated cost limits, even after placement in the scale of Development Officer Grade II, the reduction in basic pay shall start in the scale of Development Officer Grade II, by the number of stages as applicable to the relevant successive occasion.

NOTE II.—If after such reduction the basic pay falls below the minimum of the scale of Development Officer Grade II, the basic pay of such Development Officer shall be fixed at the minimum of the scale of Development Officer Grade II.

(5) The Development Officer whose basic pay has been fixed at the minimum of the scale of Development Officer Grade II, after reduction under sub-paragraph (4), shall be provided an opportunity of one year to conform to the stipulated cost limits and will be issued a warning that his services shall be liable for termination if he still continues to exceed the stipulated cost limits.

(6) If the Development Officer continues to be beyond stipulated cost limits even after bringing down his basic pay to the minimum of the scale of Development Officer Grade II and providing him an opportunity of one year under sub-paragraph (5), his services shall be terminated by an officer not below the rank of Assistant General Manager, after giving him notice of 30 days :

Provided that services of no Development Officer shall be terminated unless he is given an opportunity to appeal to the appeals committee constituted for the purpose under sub-paragraph (7) within the period of 30 days from the date of serving a notice of termination and unless the said appeals committee considers the said appeal and confirms that the services of the concerned Development Officer are liable for termination:

Provided further that the services of the concerned Development Officer shall not be terminated, if the appeals committee after considering his appeal decides that certain relief should be provided to him.

(7) The appeals committee referred to in sub-paragraph (6) shall be constituted by the Chairman of the Corporation from time to time for providing relief to Development Officer liable for termination of services under this paragraph and the said Committee shall consider the appeals having regard to the relevant factors such as factual inaccuracies in computation of premium, cost and cost ratio or sickness, accident or such individuals extenuating circumstances beyond the control of Development Officer adversely affecting the business procurement and provide such relief other than that provided in sub-paragraph (8), as may be considered necessary in each case.

(8) Any Development Officer whose services are liable to be terminated under this paragraph may, on his specific request, be appointed as clerical staff on such terms as may be decided by the Chairman of the Corporation if he is eligible and considered suitable and subject to the condition that—(i) he is at least 45 years of age but has not completed 55 years of age and has put in at least 15 years' service as Development Officer, or (ii) there are grounds of individual extenuating circumstances such as illness, injury or disablement.

(9) Where the non-core allowance of a Development Officer are reduced under sub-paragraph (2) or sub-paragraph (3) or decrements are effected under sub-paragraph (4) or his services are terminated under sub-paragraph (6), such reduction of non-core allowance or decrements or termination of services shall not be deemed to be a penalty."

5. In paragraph 12 of the said Scheme, (1) in sub-paragraph (1), clause (x) shall be omitted;

(2) after sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(1A) The Chairman of the Corporation may, from time to time, and to vary or amend the types of business listed in sub-paragraph (1), having regard to the necessity of developing certain unexplored or under-developed types of insurance. The Chairman of the Corporation may also provide for a Scheme of serial incentive for development of rural or any other specified classes of insurance, if deemed necessary and in the manner as may be decided by him."

6. For paragraph 13 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"13. Increments.—A development officer whose cost ratio for the relevant performance year does not exceed the limits stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3, shall earn increment in the relevant revised scale pay on the 1st day of January of the relevant appraisal year, provided that he has completed 12 months service in the scale in the month of January of the said appraisal year :

Provided that in case of development Officer whose cost ratio for the relevant performance year exceeds the stipulated limits, grant of increment may be considered on the basis of average cost ratio worked out on aggregate of the scheduled premium income and the aggregate cost for the relevant performance year and immediately preceding two performance year."

7. For paragraph 14 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"14. Cost based growth incentive.—A Development Officer whose cost ratio for a performance year does not exceed the limits of cost stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3 and who has procured scheduled premium income of atleast Rs. 3,00,000 during the said performance year and has registered during the said performance year a minimum increase in scheduled premium income of Rs. 60,000 over that of previous performance year shall be paid with effect from Appraisal Year 1988, cost based growth incentive equal to an amount arrived at by multiplying the increase in scheduled premium income during the performance year over the scheduled premium income of the previous performance year by difference between stipulated cost ratio and the actual cost ratio of the said Development Officer :

Provided that the maximum difference between stipulated cost ratio and actual cost ratio to be taken for calculating the cost-based growth incentive shall not exceed 5 per cent :

Provided further that the amount of cost based growth incentive shall not exceed twelve months basic pay drawn by the concerned Development Officer during the relevant performance year."

8. For paragraph 15 of the said Scheme, the following paragraphs shall be substituted, namely :—

"15 Profit incentive.—A Development Officer whose cost ratio for the relevant performance year is within the limit stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3 and whose scheduled premium income for the said performance year is not less than that of the previous performance year, shall be eligible to be considered for grant of profit incentive at the rates specified in the table below.

#### TABLE

Operating Surplus	Percentage of operating surplus to be paid as profit incentive
Below 20%	Nil
20% or more but less than 22.5%	1.25%
22.5% or more but less than 26%	2.5%
26% or more but less than 27%	3.5%
27% or more but less than 28%	4.5%
28% or more but less than 29%	5.5%
29% or more but less than 30%	6.5%
30% or more	7.5%

Provided that the profit incentive under this paragraph shall be payable to a Development Officer with effect from the Appraisal year 1988 and shall not exceed the annual basic pay drawn by him during the relevant performance year and this cost including the profit incentive and cost based growth incentive, if any, is within the limit stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3.

9. For paragraph 16 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

**"16. Provident Fund.—Every Development Officer shall contribute to the Provident Fund at the rate of 8-1/3 per cent of his basic pay with an equal contribution by the Corporation or the Company, as the case may be."**

10. In paragraph 17 of the said Scheme, after clause (b) of sub-paragraph (1), but before the proviso, the following clause shall be inserted, namely :—

**"(bb) Notwithstanding anything contained in clause (a) relating to qualifying service for admissibility of gratuity and clause (b), gratuity shall be payable to every Development Staff who has been in continuous service of the Corporation or the Company, or both, for not less than fifteen years, for each completed year of service or part thereof in excess of six months, at the rate of one month's basic pay, subject to a maximum of 15 months for service upto 30 years and for service over 30 years an additional gratuity shall be payable at the rate of half a month's basic pay for each completed year of service or part thereof in excess of six months :**

Provided that the amount of gratuity payable to a Development Staff shall be as determined above or as calculated under the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), whichever is more favourable to him.

Provided that Development Officer appointed after the date of commencement of the Amendment Scheme, 1987, shall, subject to the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), be eligible for payment of gratuity only after he has completed atleast 15 years of continuous service unless termination of the concerned Development Officer is due to death or disablement.

11. In paragraph 19 of the said Scheme, sub-item (iii) of sub-clause (b) shall be substituted by the following, namely :—

**"(iii) to prepare and issue cover notes, kutch receipts, Certificates-cum-Policies and Certificates in such classes and in such manner as may be directed by the Corporation or Company from time to time, as also to maintain expiry registers, Agency records, work reports, and the like."**

12. Paragraph 21 of the said Scheme shall be omitted.

13. In paragraph 22 of the said Scheme, for the words "the Corporation" the words "Chairman of the Corporation" shall be substituted.

14. In the said Scheme, after the Schedule, the following schedules shall be inserted, namely :—

#### "SCHEDULE A

(see paragraphs 3, 7A, 11, 13, 14, 15, 16 and 17)

##### I. Scale of Pay (Basic Pay) :

**(1) Development Officer Grade-I  
Rs. 720-60-1080-70-1500-80-2380**

**(2) Development Officer Grade-II  
Rs. 550-30-730**

**If. Dearness Allowance.—The dearness allowance will be linked to All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 1960=100), and shall be payable only when the Average All India Consumer Price Index Number for Industrial Workers is above CPI 332, on the following lines, namely :—**

- (i) For the purpose of payment of D.A. one cycle would consist of 24 points rise or fall in CPI. Each cycle would consist of 2 stages, viz. 1st stage at 8 points rise and 2nd stage at 16 points rise.**
- (ii) Development Officers drawing basic pay upto Rs. 1600 per month will be eligible to get quarterly adjustment in D.A. at the first stage viz., for every rise or fall of 8 points above 332 in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index (1960=100);**
- (iii) For Development Officers drawing basic pay of more than Rs. 1600 per month the first adjustment will be at the 2nd stage only, viz., for every block of 16 points (when the quarterly index reaches the level of 348) and the subsequent adjustment will be for the next block of 8 points (when the Average Index reaches 356). The cycle of adjustment will be repeated thereafter;**
- (iv) The rate of adjustment will be 2 per cent of the basic pay for every change of 8 points (subject to what is stated in (iii) above) in the quarterly average of the Index subject to ceiling of Rs. 31.60;**
- (v) Marginal adjustments wherever necessary shall be made to ensure that the amount of DA payable at a higher level is not less than the amount of dearness allowance payable at lower level.**
- (vi) For this purpose, quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September or December.**
- (vii) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figures which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.**
- (viii) The revision of dearness allowance corresponding to the changes in the average index for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.**

**Note.—For removal of doubt, it is clarified that the revision, if any, in dearness allowance will be effective from 1st day of February, May, August, and November in accordance with the average index for the quarters ending immediately preceding December, March, June and September respectively.**

**III. House Rent Allowance.—House Rent Allowance shall be payable to the Development Officers at the rate of 15 per cent of basic pay upto basic pay of Rs. 2000 and 10 per cent of excess over Rs. 2000 subject to a maximum of Rs. 325 per month. Provided that the Development Officers who are allotted accommodation by the Corporation or the Company shall not be entitled to any House Rent Allowance and they shall pay for the use of accommodation allotted to them an amount equivalent to 10 per cent of the basic pay or the licence fee, whichever is less.**

**City Compensatory Allowance.**—(1) The City Compensatory Allowance shall be payable at the following rates:—

Place of posting	Rate	Amount per month	
		Minimum Rs.	Maximum Rs.
(a) Cities with population exceeding 12 lakhs and urban agglomeration of Panaji and Marmugao	10% of Basic Pay	75/-	150/-
(b) Cities with population of 5 lakhs and above but not exceeding 12 lakhs, State Capitals with population not exceeding 12 lakhs and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair.	6% of Basic Pay	50/-	100/-

Note.—For the purpose of this item, the population figures shall be those in the 1981 Census Report.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-item (1), any Development Officer in receipt of an amount of Rs. 20 per month as City Compensatory Allowance as on 31st December, 1986 and not becoming eligible for City Compensatory Allowance under Amendment Scheme, 1987, shall continue to receive the said amount so long as he is posted at the same centre.

**V. Hill Station Allowance.**—The scales of hill station allowance payable to Development Officers shall be as follows:—

- (i) Posted at place situated At the rate of 10% of the basic at a height of 1500 metres pay subject to a maximum of and over, above mean sea Rs. 100/- per month. level
- (ii) Posted at places situated At the rate of 8% of basic pay at a height of 100 meters subject to a Maximum of and over, but less than 1500 meters, above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central/State Governments for their employees.

**VI. Allowance for Technical Qualifications.**—A confirmed Development Officer who qualifies or has qualified in an examination mentioned below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination or the date of confirmation or 1st January, 1987 whichever date is later, the allowances for technical qualifications mentioned below:—

Examination	Qualification allowance per month
Federation of Insurance Institutes or chartered Insurance Institute :	
(i) Licentiate . . . . .	Rs. 40/-
(ii) Completion of Associateship . . . . .	Rs. 80/-
(iii) Completion of Fellowship . . . . .	Rs. 130/-
Institute of Actuaries, London	
(i) Any three subjects . . . . .	Rs. 100/-
(ii) Any six subjects . . . . .	Rs. 130/-
Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountants :	
(i) Completion of Intermediate . . . . .	Rs. 80/-
(ii) Final Group A . . . . .	Rs. 100/-
(iii) Final Group B . . . . .	Rs. 130/-

Provided that not more than one qualification allowance shall be permissible.

The grant of allowance for technical qualifications shall not affect the seniority of the Development Officer concerned. Where the Development Officer has already been given an advance increment or any other recurring monetary benefit for having qualified in any of the said examinations, the amount of qualification allowance shall be suitably reduced or be not admissible depending on the quantum of benefit already received.

#### SCHEDULE B

(See Paragraphs 7A and 7B)

Chart of Corresponding stages for fixation of basic pay

Development Officer Grade I		Development Officer Grade II	
Existing Basic Pay Rs.	Revised Basic Pay Rs.	Existing Basic Pay Rs.	Revised Basic Pay Rs.
1	2	3	4
250	720	175	550
265	780	185	580
280	840	195	610
295	900	205	640
315	960	215	670
335	1020	225	700
355	1080	240	730
375	1150		
400	1220		
425	1290		
450	1360		
475	1430		
500	1500		
525	1580		
555	1660		
585	1740		
615	1820		
645	1900		
675	1980		
710	2060		
745	2140		
780	2220		
815	2300		
850	2380		

[F. No. 114(2)/Ins.IV/87]

A.K. PANDYA, Addl. Secy. (Insurance)

